मुद्रास्फीति (Inflation)

मुद्रस्फीति अथवा मुद्रा प्रसार वह स्थिति है, जिसमें कीमत-स्तर में वृद्धि होती है एवं मुद्रा की क्रय-शक्ति अर्थात् मुद्रा का मूल्य कम होता है।

यह वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख (ऋण) की मात्रा में वृद्धि होती है एवं परिणाम स्वरूप मूल्य-स्तर में निरंतर वृद्धि होने लगती है।

मुद्रास्फीति की परिभाषा कीन्स के अनुसार–

''वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिन्दु के बाद उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिन्दु से पूर्व उत्पन्न होने वाली मुद्रा स्फीति प्रेरणात्मक होती है अर्थात् अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है।''

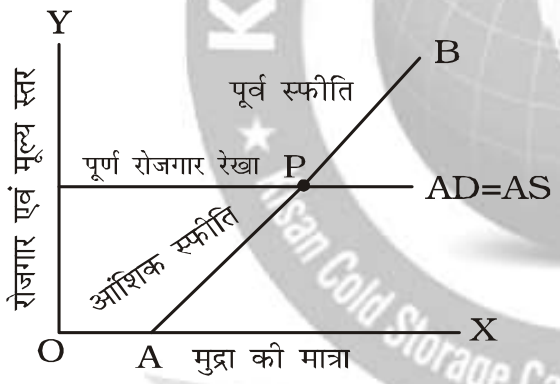

(Disinflation) (विस्फीति/ अनस्फीति) – जब RBI मौद्रिक नीति के द्वारा एवं सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रा-आपूर्ति को कम करे जिससे मुद्रास्फीति का नियंत्रण होता है एवं इसे विमुद्रास्फीति विस्फीति कहते हैं।

अवस्फीति (Deflation) – जब सामान्य कीमत स्तर (सभी वस्तुएँ एवं सेवाओं) की कीमतें लगातार कम हों एवं मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़े।

पुनःस्फीति/प्रत्यवस्फीति (Reflation)–

RBI एवं GOI द्वारा मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना, जिससे अवस्फीति का नियंत्रण हो सके, पुनः स्फीति कहलाता है।

मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

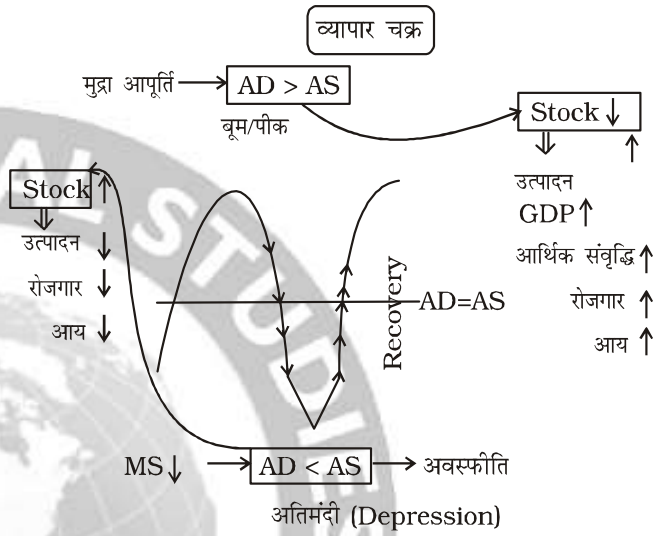

व्यापार चक्र–व्यापार चक्र की अवस्थाएँ तेजी और मंदी का चक्र लगातार चलता रहता है। मूल्य बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं। रोजगार बढ़ता-घटता रहता है।

व्यापार चक्र की अवस्थाएँ–

1. Recovery (पुनरुद्धार)
2. पूर्ण रोजगार (Full Employment)
3. तेजी (बूम) (Boom/Peak)
4. मंदी / अवरोध (Recession)

1. **मंदी की अवस्था (Recession)**–इसमें देश की व्यावसायिक क्रियाओं का स्तर नीचे गिर जाता है। इस समय रोजगार एवं उत्पादन स्तर में भारी गिरावट होती है।
2. **पुर्नरूधार (Recovery)**–जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा-आपूर्ति को बढ़ाया जाता है जिससे व्यावसायिक क्रियाओं में वृद्धि होती है एवं अर्थव्यवस्था में संतोषजनक स्थिति होती है।
3. **पूर्ण रोजगार की अवस्था–इसे सम्पन्नता (Prosperity)** की अवस्था भी कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होता है–

(1) आर्थिक क्रिया का अनुकूल स्तर पर पहुँचना।

(2) पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। अर्थात कार्य करने की शक्ति एवं इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो।

4. **तेजी की अवस्था**–पूर्ण रोजगार के बाद भी विनियोग (खर्च) के लगातार बढ़ने के कारण तेजी जैसी अवस्था अर्थात् मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है।

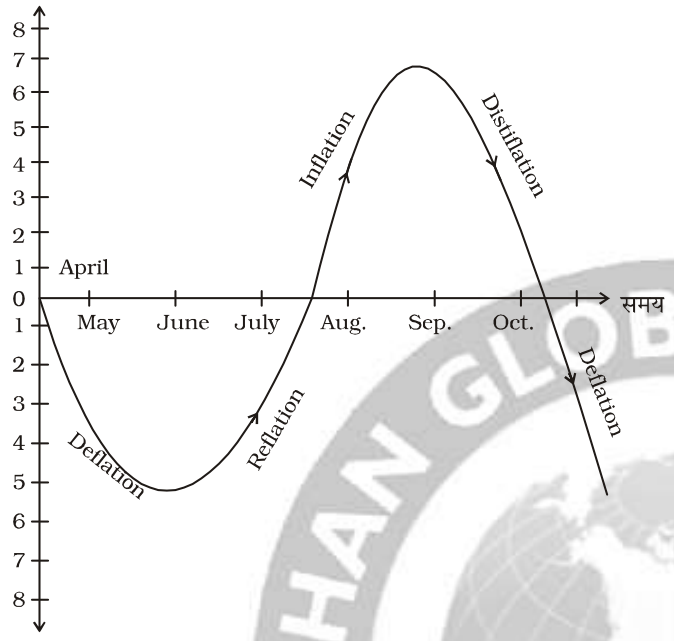

मुद्रास्फीति जनित मंदी (Stagflation)

यह अर्थव्यवस्था की वह अवस्था है जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ होती है अर्थात् जब सामान्य कीमत-स्तरों में वृद्धि हो एवं रोजगार कम हो अथवा जब दोनों सामान्य कीमत स्तर एवं बेरोजगारी में वृद्धि हो।

⇒ इसमें कीमतों की वृद्धि की दर आर्थिक संवृद्धि दर से अधिक होता है।

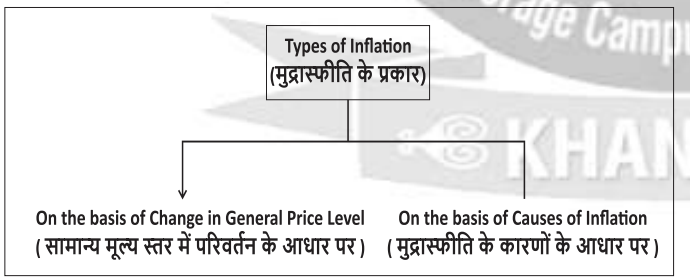

मुद्रास्फीति के प्रकार (कीमतों में परिवर्तन के आधार पर)

1. **रेंगती हुयी /मंद मुद्रास्फीति**–यह मुद्रास्फीति का सबसे हल्का रूप है, जिसे मृदु-मुद्रास्फीति या निम्न मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है।

⇒ इसमें सामान्य कीमत-स्तर 2 - 3% तक बढ़ता है। एवं इससे अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होता।

2. **चलती / घूमती मुद्रास्फीति**–जब सामान्य कीमत-स्तर 4 - 5% की दर से बढ़ता है एवं इसे मध्यम मुद्रास्फीति भी कहते हैं।

⇒ यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होता है। क्योंकि इस दौरान आर्थिक गतिविधियाँ, रोजगार, आय आदि में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. **दौड़ती मुद्रास्फीति**–जब सामान्य कीमत-स्तर 9% तक बढ़ता है जिसे दौड़ती मुद्रास्फीति कहते हैं। एवं इसे नियंत्रित करने की अति-आवश्यकता होती है क्योंकि अत्यधिक मुद्रास्फीति होने कपर आर्थिक क्रियाओं में विघटन होता है एवं इसे नियंत्रित करने में असुविधा होती है।

4. **कूदती/द्रुत (Galloping) मुद्रास्फीति**–जब सामान्य कीमत-तसर 2 या 3 अंकों में बढ़ता है।

⇒ इससे व्यवसाय और कर्मचारियों की आय एवं लागत पर प्रभाव पड़ता है। एवं इस समय विदेशी निवेशक भी निवेश करने से बचते हैं।

5. **अति/अधि मुद्रास्फीति Hyper Inflation**— जब सामान्य कीमत स्तर 1000% से भी अधिक दर से बढ़े अर्थात् इस दौरान आर्थिक गतिविधियों संम्पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती हैं एवं सरकार नियंत्रित करने में असमर्थ रहती है।

⇒ अत्यधिक कीमतों के बढ़ने के कारण मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय-शक्ति खत्म हो जाती है एवं लोगों का मुद्रा पर से विश्वास खत्म हो जाता है।

⇒ यह सर्वप्रथम I World War के बाद 1923 में Germany में देखा गया, 1946 हंगरी, जिम्बाम्बे (2004-09 एवं हाल ही में वेनेजुएला (2018) में।

⇒ **अधि-मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय–**

1. विमुद्रीकरण
2. अल्पकालिक समय के लिए दूसरे देशों की मुद्राओं को घरेलू मुद्रा घोषित करना।
3. आवश्यक वस्तुएं जैसे-खाद्य एवं ईंधन पदार्थ की कीमतों को सरकार के द्वारा नियमित / कम करना।

मुद्रास्फीति का लक्ष्य–उर्जित पटेल समिति के सुझावों के तहत 2016 से भारत में मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का ढाँचा तैयार किया गया एवं इसके तहत भारत-सरकार RBI से सलाह लेकर मुद्रास्फीति के लक्ष्य को 5 वर्षों के लिए निर्धारित करती है।

सर्वप्रथम 2016-21 एवं दूसरी बार 2021-2026 जिसमें मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% $\pm$ 2% तय किया गया है।